नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

7 राज्यों ने मिलकर बनाई अपराध रोकने की रणनीति

- इंदौर में प. क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक
- अपराध पर रीयल टाइम सूचना साझा करने पर बनी सहमति

नव भारत न्यूज

इंदौर, 7 अगस्त. बदलते अपराध के स्वरूप और अंतरराज्यीय अपराधों से निपटने के लिए सात राज्यों की पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार की है.

इंदौर में हुई पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक में साइबर अपराध, संगठित अपराध, ड्रग नेटवर्क और आगामी सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सूचना साझा करने पर सहमति बनी.

पुलिस मुख्यालय की अधिकृत जानकारी के अनुसार 13वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने की. इसमें मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए. बैठक में अंतरराज्यीय अपराधों की रोकथाम, राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई. सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने अपराध से जुड़ी सूचनाओं के रीयल टाइम आदान प्रदान, राज्यों के बीच लगातार संपर्क और प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त कर नियमित समीक्षा करने पर सहमति जताई.

सिंहस्थ-2028 की सुरक्षा पर भी मंथन

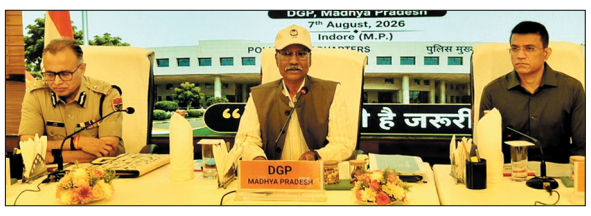

ड्रग नेटवर्क और संगठित अपराध पर संयुक्त अभियान

बैठक में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन और बिक्री से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया. बैठक में यह भी निर्णय लिया कि संबंधित राज्य जल्द संयुक्त कार्ययोजना तैयार कर विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए वांछित और इनामी अपराधियों का डाटाबेस साझा किया. भविष्य में संयुक्त अभियान चलाने और अपराधियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी.

दबंग दुनिया पर 48 करोड़ की कर देनदारी

फर्जी सर्कुलेशन और विज्ञापनों से आय दिखाने का आरोप, 75 हजार का जुर्माना

नव भारत न्यूज

इंदौर, 7 अगस्त. दबंग दुनिया पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (डीडीपीएल) के खिलाफ सेंट्रल जीएसटी विभाग ने करीब 48 करोड़ रुपए की कर देनदारी तय की है. विभाग के संयुक्त आयुक्त योगेश पांडुरंग ने जारी आदेश में कंपनी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

कार्रवाई में अखबार के प्रसार और विज्ञापन से जुड़ी आय को लेकर अनियमितता का उल्लेख किया है. विभाग की जांच में दावा किया है कि दबंग दुनिया पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अखबार के प्रसार की संख्या वास्तविक आंकड़ों से अधिक दर्शाई गई. इसके आधार पर 5.73 करोड़ रुपए की आय बताई गई. वहीं, कथित फर्जी विज्ञापनों के माध्यम से 5.93 करोड़ रुपए की आय दर्शाने का भी उल्लेख किया है. इन दोनों मदों में बताई गई 11.66 करोड़ रुपए की आय को आधार बनाकर विभाग ने कर देनदारी निर्धारित की. विभाग ने 3.68 करोड़ रुपए जीएसटी, 65 लाख रुपए सेस और 44.50 करोड़ रुपए सेस 2 सहित करीब 48 करोड़ रुपए की मांग तय की है.

> जांच में डीडीपीएल और ईटीसीएल (ऐलोरा टोबेको) के बीच कारोबारी संबंध होने का भी उल्लेख किया है. विभाग का दावा है कि दोनों संस्थाओं के बीच जुड़ाव था और डीडीपीएल के माध्यम से ऐलोरा टोबेको से जुड़ी कुछ गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. आदेश में अखबार के कुछ कर्मचारियों और रिपोर्टरों के नाम पर कथित फर्म संचालित होने का भी जिक्र है. इसमें एक क्राइम रिपोर्टर के नाम पर फर्म, एक कर्मचारी को दूसरी कंपनी में निदेशक बनाए जाने और एक अन्य कर्मचारी के माध्यम से कथित फर्जी पते पर कंपनी पंजीकृत कराने की बात कही गई है. विभाग ने कर सलाहकार के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति को भी संस्थान से जुड़ा कर्मचारी बताया है.

खादी हमारे स्वाभिमान, स्वदेशी का प्रतीक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 अगस्त. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भोपाल के जवाहर चौक स्थित सरस्वती नगर के खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज एवं वस्त्र खरीदा.

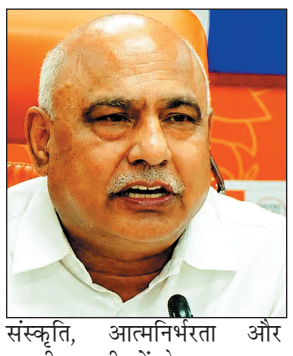

खण्डेलवाल ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि हमारे स्वाधीनता संग्राम की आत्मा और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को स्वदेशी, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया था. आज भी खादी भारतीय संस्कृति, आत्मनिर्भरता और स्थानीय कारीगरों के सम्मान का प्रतीक बनी हुई है. मध्यप्रदेश के चंदेरी, महेश्वरी, नंदना प्रिंट और बाग प्रिंट जैसी समृद्ध हस्तकरघा परंपराएं हमारे बुनकर साथियों की अद्भुत प्रतिभा, परिश्रम और सांस्कृतिक विरासत की पहचान हैं. कृषि के बाद हैंडलूम एवं बुनकर उद्योग देश में रोजगार का सबसे बड़ा आधार है. हमारे पारंपरिक वस्त्र न केवल भारतीय संस्कृति और विरासत के संवाहक हैं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का भी प्रमुख साधन हैं.

> भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 7 अगस्त भारतीय इतिहास में स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणादायी तिथि है. वर्ष 1905 में इसी दिन कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद हुआ था. उसी ऐतिहासिक विरासत को स्मरण करते हुए देशभर में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 45 लाख बुनकर हैंडलूम उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिनमें लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं हैं.

मंत्रालय में दिनभर रहा अफसरों का टोटा

भोपाल. मंत्रालय में शुक्रवार को ऐसा पहली बार हुआ, जब यहां पदस्थ बड़े अफसरों का टोटा रहा. मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के लिए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, सीएम के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित कमोबेश सभी आला अधिकारी मंत्रालय से बाहर निकले. इनमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल थे. आम दिनों में इन आला अफसरों के केबिन में मीटिंग्स की गहमागहमी बनी रहती है, लेकिन शुक्रवार को ये खाली रहे. ज्यादातर अफसरों ने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों, निर्माण कार्यों की जमीनी पड़ताल की.

गलत जानकारी देने पर एसडीओ ने कोर्ट में मांगी माफी

हाईकोर्ट ने सरकार के साथ नगर निगम को भी इलाज खर्च उठाने के दिए निर्देश

नव भारत न्यूज

इंदौर, 7 अगस्त. अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में इलाज खर्च को लेकर पेश किए गए शपथ पत्र में हुई गलती को लेकर एसडीओ ने हाईकोर्ट में माफी मांगी. कोर्ट को बताया कि जिन भुगतानों को पूरा बताया गया था, वे अभी प्रक्रिया में हैं. हाईकोर्ट ने घायलों के इलाज खर्च की जिम्मेदारी सरकार के साथ नगर निगम को भी उठाने के निर्देश दिए हैं.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के आदेश के पालन में जूनी इंदौर के एसडीओ घनश्याम धनगर कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि शपथ पत्र में गलती से यह उल्लेख हो गया था कि अहमदाबाद के जाइडस अस्पताल के बकाया भुगतान किए जा चुके हैं, जबकि वास्तव में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि संबंधित राशि एक सप्ताह में जमा कर दी जाएगी.

गैस पाइपलाइन विस्फोट मामला

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि हादसे में घायल लल्लू पटेल, विजय पटेल, सुभाष सिंह ठाकुर और गोपाल मलांकर के बॉम्बे अस्पताल और अरबिंदो अस्पताल में हुए इलाज खर्च की राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. संबंधित अस्पतालों के माध्यम से एक सप्ताह में भुगतान की कार्रवाई पूरी करने की बात कही गई. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई में अंतरिम मुआवजे के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी. वहीं, इंदौर नगर निगम की ओर से बताया कि बॉम्बे अस्पताल प्रबंधन को घायलों की निःशुल्क ड्रेसिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा है.

इनका कहना

कोर्ट ने गलत जानकारी वाले शपथ पत्र पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे. हमने कोर्ट को बताया है कि भुगतान प्रक्रिया में है और जल्द पूरी कर दी जाएगी.

घनश्याम धनगर, एसडीओ, जूनी इंदौर

> **इलाज खर्च में देरी पर कोर्ट ने जताई चिंता...**
>
> हाईकोर्ट ने पाया कि घायलों को भुगतान में देरी हो रही है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण घायलों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिए कि इलाज और मुआवजे से जुड़े खर्च की जिम्मेदारी राज्य सरकार के साथ इंदौर नगर निगम भी उठाएगा. सुनवाई के दौरान अवंतिका गैस लिमिटेड को भी पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने तीन कार्य दिवस में नोटिस जारी करने और एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.

एसीएस मण्डलोई ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 अगस्त. औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित की जा रही अधोसंरचना राज्य के औद्योगिक विकास की आधारशिला है. निवेशकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ श्रमिकों एवं कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर कार्य एवं आवासीय वातावरण सुनिश्चित करना भी जरूरी है.

इसी दृष्टिकोण के साथ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने शुक्रवार को मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में संचालित प्रमुख विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. मंडलोई ने मंडीदीप में विकसित किए जा रहे वर्किंग वूमेन हॉस्टल परियोजना का निरीक्षण किया. उन्होंने परियोजना के साइट ले-आउट का विस्तार से अवलोकन किया, जहां आठ हॉस्टल ब्लॉक्स का कार्य प्रगति पर है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर में कार्यरत महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिम जैसी सुविधाएं विकसित किए जाने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाए, जिससे यह परिसर केवल आवासीय सुविधा तक सीमित न रहकर समग्र सुविधाओं से युक्त आधुनिक परिसर के रूप में विकसित हो सके. अपर मुख्य सचिव ने मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किए जा रहे स्पोर्ट्स पार्क का भी निरीक्षण किया. उन्होंने परियोजना की प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में खेल एवं मनोरंजन संबंधी अधोसंरचना कर्मचारियों और श्रमिकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

मण्डीदीप में चल रही विभिन्न परियोजनाओं से हुए रूबरू

निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश

साढ़े तीन सौ करोड़ के स्कूल ड्रेस टेंडर पर अंतरिम रोक

जबलपुर, 7 अगस्त. मप्र हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को वितरित होने वाली यूनिफार्म की आपूर्ति के लिए जारी करीब 350 करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जवाब दाखिल होने तक संबंधित टेंडर को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। उक्त आदेश अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पावरलूम बुनकर संघ सहित तीन बुनकर संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा 3 जून 2026 को जारी टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इसे मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम, 2023 के प्रावधानों के विपरीत बताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 1993 से राज्य स्तरीय पावरलूम सहकारिता समिति को प्रदेश के सरकारी स्कूलों की यूनिफार्म आपूर्ति के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करने की व्यवस्था रही है।

दोस्ती में ठगी : 53 लाख का 22 चक्का ट्रक हड़पकर कटवाया

ग्वालियर, 7 अगस्त. शहर के हजीरा थाना क्षेत्र में दोस्ती का फायदा उठाकर 53 लाख रुपए कीमत का नया 22 चक्का ट्रक हड़पने का मामला सामने आया है.

आरोपी ने हर महीने डेढ़ लाख रुपए किराया देने का झांसा दिया था, लेकिन कुछ महीने भुगतान करने के बाद ट्रक का जीपीएस बंद कर उसे कटवाकर बेच दिया. पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़ित कारोबारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. घटना हजीरा थाना क्षेत्र के ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के पास, मुरैना रोड वर्ष 2024 से 2025 के बीच की है. पीड़ित राजेंद्र सिंह राजावत ,आदित्यपुरम निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी है. आरोपी राजेश शर्मा गोपालपुरा, अमायन, भिंड निवासी ट्रांसपोर्टर ने 10 सितंबर 2024 को 1.50 लाख रुपए प्रतिमाह के अनुबंध पर नया ट्रक किराए पर लिया था. शुरुआत में 6 महीने किराया देने के बाद आरोपी ने भुगतान बंद कर दिया, ट्रक को कटवाकर बेचने की धमकी दी. थाने में सुनवाई न होने पर कोर्ट के निर्देश पर हजीरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जनहितैषी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के प्रथम शिविर में 160 आवेदनों का हुआ निराकरण

एक ही स्थान पर आमजन को मिलेंगे कई लाभ : शुक्ल

भोपाल, 7 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार रीवा जिले में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान आरंभ हो गया है. सिरमौर विकासखण्ड में आयोजित अभियान के प्रथम शिविर में आम जनता से मिले 322 आवेदन पत्रों में से 160 का मौके पर निराकरण किया गया.

शिविर में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. शिविर में आम जनता को एक ही स्थान पर कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. जिन कार्यों के लिए आम जनता को कार्यालयों में भटकना पड़ता है उनका लाभ शिविर में किया जा रहा है. आम जनता की कठिनाईयाँ दूर करना सुशासन की पहल है. शिविर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जन विश्वास अभियान में अधिकारी आम जनता से संवाद करने के साथ-साथ स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवाद कर रहे हैं. अभियान के दौरान शासन की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग होगी.

> शिविर में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शिविर के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान से प्रशासनिक गतिशीलता और मानीटरिंग बढ़ेगी. यह अभियान सुशासन को बढ़ावा देने में सफल होगा. जनसंवाद से आम जनता की कठिनाईयों को दूर किया जा रहा है. आर्थिक विकास के लिए उद्यमियों के साथ उद्यम संवाद भी किया जा रहा है. जिला और विकासखण्ड स्तर के सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं की शिविर के माध्यम से मानीटरिंग कर रहे हैं.